जा सके । अभी जम्मू काश्मीर सरकार से हमें इतनी ही इत्तिला मिली है कि उस पर अमल हो रहा है, उन्होंने अभी यह नहीं बतलाया है कि वे क्या क रहे हैं ?

बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए विशेष प्राधिकरण

*667. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए विशेष प्राधिकरण के बारे में 13 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न सं० 273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजर अथवा ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु विशेष प्राधिकरण बनाने में क्या कठिनाई है; और

(ख) क्या बंजर भूमि को शीघ्र कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता पर सरकार विचार करेगी ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The barren lands like mountains, deserts, etc. cannot be economically brought under cultivation. Reclamation of culturable waste land including old fallows is being organised by the State Governments and there is no need for creating a special authority for reclaiming such lands at the Centre.

(b) Yes, Sir.

श्री रामधारी शास्त्री : मंत्री महोदय ने अपने जबाब में बताया है कि इस तरह की भूमि का कल्टीवेशन में आना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी --यदि इस तरह की भूमि को रिक्लेम किया जाय तो इस पर प्रति हैक्टेअर क्या खर्च पड़ेगा ?

क्या आप यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह की पुरानी ऊसर और बंजर भूमि पर, किस-किस राज्य सरकार ने कितनी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी भूमि पर कब्जा, कर लिया है और उस को खेती के योग्य बना दिया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह एक किस्म की जमीन नहीं है, इस में से कुछ जमीनें पहाड़ी इलाके में आती हैं, कुछ दूसरे इलाकों में आती हैं---इस लिये इन पर क्या खर्चा आयेगा, यह बतलाना मुश्किल है । अलग-अलग किस्म की जमीनों पर अलग-अलग खर्चा आता है ।

जो रैबीन लैण्ड है, कटी-फटी जमीनें हैं---उस में राजस्थान ने 865 हैक्टेयर, उत्तर प्रदेश ने 2158 हैक्टेयर, मध्य प्रदेश ने 4301 हैक्टअर, गुजरात ने 3744 हैक्टेअर, कुल 11068 हैक्टेअर जमीन रिक्लेम की है : अलकेलीन-सायल की उत्तर प्रदेश ने 4 हजार हैक्टेअर, पंजाब ने 15490 हैक्टअर इस तरह से कुल 27890 हैक्टेअर जमीन को रिक्लेम किया गया है :

श्री रामधारी शास्त्री : मंत्री जी ने अपने जबाब में कहा है कि केन्द्रीय सरकार कोई केन्द्रीय अथारिटी बनाने की जरूरत नहीं समझती । इस के सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं---जैसा कि उन्होंने 13 मार्च, को जबाब दिया था---सारे देश में 179 लाख हैक्टेअर ऐसी जमीन है, जिस को कृषि योग्य बनाया जा सकता है । इस देश की स्थिति को देखते हुए---हमारी दृष्टि से करीब-करीब 3 करोड़ 38 लाख हैक्टअर ऐसी जमीन है, जिस को करीब 1 करोड़ लोगों को एलाट किया जा सकता है जिस से इस देश की बड़ी भारी जनसंख्या की बेरोजगारी का समाधान हो सकता है । इस के अलावा इस भूमि की रिक्लेम करने में लगभग 50 लाख लोगों को एक साल तक

काम करते रहना होगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय कोई इस तरह की योजना बनायेंगे कि सारे देश की ऊसर और बंजर भूमि खेती योग्य हो सके? क्योंकि जो मौजूदा माडर्न मशीने है, उन को खरीदना किसी भी राज्य सरकार के बूते के बाहर है। ये मशीनें बहुत कम मिलती है और उन की कीमतें भी बहुत ज्यादा है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : लैंड इम्प्रूवमेंट आइटम नं० 18 लिस्ट 2 सैवथ शैड्यूल्ड कास्टीट्यूशन मे आता है। इसलिए काम उन्ही को करना है। जहा तक 169 लाख हैक्टेअर भूमि जो काबले काश्त हो सकती है उसका जवाब वह शायद समझे नही। कल्चरेवल वैस्ट लैंड टोटल जो है वह 169 लाख हैक्टर है। बहुत पैसा खर्च करके और बहुत मेहनत करके बीस से तीस परसेंट तक यह काश्त में लाई जा सकती है बाकी। जमीन काश्त में नही लाई जा सकती है। उस पर भी बहुत खर्च करना पड़ता है।'

श्री रामधारी शास्त्री : मंत्री महोदय ने पहले जो जवाब दिया था उस से उन्होने यह कहा था बंजर भूमि के अन्तर्गत पहाडी रेगिस्तानी आदि जैसी अकृष्य भूमि है, जिसे मितव्ययी रूप से कृषि के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। तथापि लवणीय, क्षारी ऊबड़-खाबड़ भूमि, जल मग्न क्षेत्र और अन्य परती भूमि जैसी कुछ बेकार भूमि ऐसी है, जिसे कुछ सीमा तक सुधारा जा सकता है। कृषि योग्य परती भूमि का अनुमान 169 लाख हैक्टर के लगभग लगाया गया है।

आज वह कैसे इसमें अलग बात कह सकते हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : तब भी यही कहा था कि इस में कुछ ऐसी बीस से तीस परसेंट आराजी है जो खेती के काबिल बनाई जा सकती है। लेकिन खर्च काफी आएगा।

श्री छ बि राम अली : मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर चम्बल रेवाइंज की करोड़ो एकड़ भूमि है। मंत्री महोदय ने बताया है कि पांच हजार एकड भूमि मध्य प्रदेश मे बीहड़ की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार इस स्थिति मे नही है कि इन रेवाइज को रिक्लेम करके कृषि योग्य बना सके। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेगे कि जो चम्बल के बीहड है जहा पर डाकू पैदा हो जाते है और अब पुनः पैदा होने लगे है उनको रिक्लेम करके हरिजनो और आदिवासियों को पट्टे पर बाट दिया जाए। अगर आप रैवाइज का रिक्लेम नही करा सकते है तो क्या आप इन रेवाइज और बीहडों को हरिजनो और आदिवासियो को पट्टे पर देने की व्यवस्था करेगे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मने अर्ज किया था कि यह हमारे अधिकार मे नही है कि हम पट्टे पर दे दे। यह राज्य सरकार को करना है। रिक्लेम भी उन्होने करना है। हां यह जरूर है कि रेवाइज के रिक्लेमेशन के लिए हम सौ फीसदी सबसिडी देते है, टोटल सबसिडी देते है। थोड़ा सा काम उस पर शुरू हुआ है। पिछले साल में बारह सौ हैक्टर रकबा उस मे रिक्लेम किया गया है।

SHRI VASANT SATHE: What is the total acreage of land that would be available in the Chambal ravines as well as other areas? Is there any proposal that an authority like the World Bank or the U.N. Development Fund should come forward to help in a large programme of reclamation of this land, and what is the Government's attitude thereto?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: So far as the first part of the question is concerned, it does not arise from the main question. That does not relate to Madhya Pradesh, otherwise I would have given the acreage. Regarding the second part, if a particular scheme is posed, we can surely take the assistance of monetary agencies like the World Bank.

MR. SPEAKER: The question is large enough to cover Madhya Pradesh, but probably you require notice.

SHRI VASANT SATHE: The question is about a special authority for conversion of barren land into cultivable land. We must have an idea of the acreage of the land I have asked only about that.

SHRI SURJIT SINGH BARLANA: I can give he acreage for the whole country Barren land—23 56 million hectares, culturable waste land 16 86 million hectares

श्रीमती कमला बहुगुणा : मंत्री महोदय ने कहा है कि पच्चीस, तीस पससेंट ऐसी जमीन है जिसे पैदावार के काबिल बनाया जा सकता है। मैं जानना चाहती हू कि अगले दो साल मे कितनी पैदावार के काबिल बनाई जाएगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह राज्यों पर निर्भर करता है। काम उन्हीं को करना होता है हम नही करते हैं। एक्जीक्यूट उनके जरिये से होता है।

Local Printing by Ministries/Departments

668. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to lay a statement showing:

(a) the total amount spent by the different Ministries/Departments on local printing during the years 1975, 1976 and 1977; and

(b) the steps taken for reducing this expenditure in the coming years by Government?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) स्थानीय छपाई के काम को कम करने के लिए उठाये गए मुख्य कदम ये हैं :—

(i) भारत सरकार मुद्रणालयों की मौजूदा छपाई क्षमता मे वृद्धि करना,

(ii) छोटे कार्यों पर लगी रोक को हटाना जहा केवल सीमित सख्या मे प्रतिया छापी जानी होती है।

श्री मोहन लाल पिपिल: किस-किस साल मे कितनी राशि खर्च हुई है इसका उत्तर मत्री महादय ने यह दे दिया है कि इनफर्मेशन कनैक्ट की जा रही है। मैं कहना चाहता हू कि इस मामले मे करोडो रुपये का गोलमाल है। मै जानना चाहता हू कि कब तक वह इनफर्मेशन कलैक्ट कर लेंगे ?

श्री राम किंकर : जैसे ही सूचना आ जाएगी सदन पटल पर रख दी जाएगी।

MR SPEAKER: 10 days notice was given to you

श्री मोहन लाल पिपिल बहुत से भारत सरकार के पास रिप्रिजेंटेशन आए है कि नई प्रैसिस खोली जाये, स्टाफ बढाया जाए। मै जानना चाहता हू कि भारत सरकार इस मामले मे क्या कुछ विचार कर रही है? कितनी और प्रैसिस लगाने का या स्टाफ बढ़ाने का उसका विचार है ताकि यह जो घोटाले हो रहे है इनको रोका जा सके ?

श्री राम किंकर : नई प्रैस खोलने का सवाल नही है। कुछ मशीनें लगा रहे हैं जिससे हमारी प्रैस क्षमता बढ़ जायगी और जो दिक्कत आ जाती है वह दूर हो जाएगी (व्यवधान)।